International Journal of Applied Research 2016; 2(1): 825-827

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(1): 825-827
www.allresearchjournal.com
Received: 12-11-2015
Accepted: 19-12-2015

मो० मोकर्रम अली
शोधार्थी, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
मो० मोकर्रम अली
शोधार्थी, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

1947 ई. की भारत छोड़ों आंदोलन में समानांतर सरकार

मो० मोकर्रम अली

सारांशः
भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कुछ हिसों में समानान्तर सरकारों की स्थापना। विद्रोही 'राष्ट्रीय सरकार' का सर्वोत्तम विवरण मिदनापुर के तमलुक उपसभांग में मिलता है। इसके इतिहासकार सतीश सामंत जैसे स्थानीय कांग्रेसी नेता है। जो तमलुक जातीय के पहले 'सर्वाधिनायक' थे। तमलुक उपसभांग में पहली झड़प 8 सितंबर को हुई जब गाँव वालों ने पहल करके दानीपुर के एक मिल मालिक द्वारा चावल भेजें जाने के प्रयत्न को विफल किया और फिर राष्ट्रवादी सेवकों से मदद माँगी। 29 सितंबर को बड़े सुयोनिजीत ढंग से संचार–साधनों पर और पुलिस थानों पर एक साथ हमलें हुए। हमलें के स्थल तमलुक, महिषादल, सुताहाट और नंदीग्राम थे। किन्तु अन्य स्थानों पर भारी रक्त पात ह ुआ एक ही दिन में 44 लोग मारे गए। 17 सितंबर 1942 को स्थापित भूमिगत ताम्रलिप्त जातीय सरकार का प्रमुख कार्य हो गया। बाद में इस इस सरकार कि शाखाएँ, सुताहट, नंदीग्राम, महिषादल में भी स्थापित कि गई।

प्रस्तावनाः
भारत के इतिहास में 1942 की अगस्त क्रान्ति एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति का नारा था। 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' और सचमुच ही एक क्षण तो ऐसा लगने लगा कि अब अंग्रेजों को भारत से जाना ही पड़ेगा। द्वितीय विश्वयुद्ध में जगह–जगह मित्रराष्ट्रों की पराजय से अंग्रेजों के हौसले पहले से ही चूर हो गए थे और उस पर यह 1942 की क्रांति। ऐसा लगने लगा कि अंग्रेजी साम्राज्य अब टूट कर बिखरने ही वाला है। अंग्रेजों ने भारतीयों से सहायता पाने के लिए यह प्रचार किया कि भारतीय स्वयं ही अपने देश के मालिक हैं और उन्हें आगे बढ़कर अपने देश की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि भारत पर भी जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ गया था। 1942 ई. में जब जापान प्रशांत महासागर को पार करता हुआ मलाया और बर्मा तक आ गया तो ब्रिटेन ने भारत के साथ समझौता कर लेने की बात पर विचार किया। अंग्रेजों को डर था कि कहीं जापान भारत पर भी आक्रमण न कर दे।

लेकिन गाँधीजी का विचार था कि अंग्रेजों की उपस्थिति के कारण ही जापान भारत पर आक्रमण करना चाहता हैए इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने तथा भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने की माँग की। यदि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने के लिए तैयार हो जाती तो भारत युद्ध में सहायता दे सकता था।

इसके अतिरिक्त युद्धकालीन व्यवस्था के विषय में इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि युद्ध के दौरान भारत के प्रति रक्षा विभाग पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा, परंतु भारत कि सैनिक तथा आर्थिक साधनों को संगठित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर रहेगी।

क्रिप्स के इस प्रस्ताव के संदर्भ में डॉ. सीतारमैया ने लिखा है "इनमें प्रत्येक दल को प्रसन्न करने वाली बाते थीं। कांग्रेस को प्रसन्न करने के लिए इनकी पूर्व भूमिका में औपनिवेशिक स्वराज्य तथा ऐसी विधान परिषद का उल्लेख था जिसे प्रारम्भ में ही ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से पृथक हो जाने का अधिकार दिया गया था। मुस्लिम लीग के बड़ी बात यह थी कि किसी भी प्रांत को भारतीय प्रांत को भारतीय संघ से अलग हो जाने काहक था। नरेशों को भी ऐसी आजादी प्रदान कि गई थी।'' फिर भी क्रिप्स प्रस्ताव किसी को भी संतुष्ट न कर सका।

महात्मा गांधी ने तो सर क्रिप्स से यह तक कह दिया, "यदि आपके प्रस्ताव यंही थे तो आपने आने का कष्ट क्यों किया। यदि भारत के संबंध में आपकी यंही योजना है तो आपको मेरा परामर्श है कि आप अगले ही हवाई जहाज से इंग्लैंड लौट जाएं।

परंतु स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्वराज की मांग जोर पकड़ रही थी। इसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया जिसने स्थिति को और भी उलझा दिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा ब्रिटिश–भारत के युग में शामिल होने की घोषणा कर दी गयी। इससे पहले न कांगेस नेताओं से और न ही किसी प्रांतीय सरकार से कोई राय ली गयी. युद्ध में जाने की इस एकतरफा घोषणा को राष्ट्रवादियों ने बिल्कुल ही अनुचित माना एवं इसे खारिज कर दिया।

तत्पश्चात कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सभी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। इससे अंग्रेजी हुकूमत और कांग्रेस नेताओं के बीच कटुता और बढ़ गयी। राष्ट्रवादियों एवं कांग्रेस नेताओं के समक्ष जबरदस्त दुविधा का यह क्षण था. हम एकतरफ अपनी आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने उदारवादी अतंरराष्ट्रीय कूटनीतिक दृष्टिकोण से हमारा फासिज्म और नाजिज्म का विरोध करना लाजिमी था।

युद्ध शुरू होने के कुछ दिनों तक आंदोलन के अगले स्वरूप एवं तीव्रता के विषय पर असमंजस एवं अनिश्चितता की स्थिति रही। 1940 के मई से 1941 के प्रारंभ तक विश्व युद्ध के 'बैटल ऑफ ब्रिटेन' में जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन पर अंधाधुंध बमबारी करके उसे ध्वस्त करने की योजना प्रभावी हो रही थी। ब्रिटेन की पराजय के कयास लगने लगे थे। ऐसे समय में गांधी ने स्थिति की नजाकत को समझते हुए कहा था कि ब्रिटेन की राख से निकली भारत की स्वतंत्रता पाना हमारा उद्देश्य नहीं है।

स्थिति को सुलझाने एवं नियंत्रित करने का प्रयास हुआ था विफल मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से कांग्रेस नेताओं से वार्ता कर स्थिति को सुलझाने एवं नियंत्रित करने का प्रयास भी विफल साबित हुआ। मुख्य रूप से स्वराज के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं तय रहने और सिर्फ डोमिनियन दर्जा ही देने की बात राष्ट्रवादियों को मंजूर नहीं थी।

इस पर, यह सब भी युद्ध समाप्ति के बाद मिलने की बात कही गयी। इस पर गांधी जी ने इसे डूबते बैंक का पोस्ट–डेटेड चेक बता कर क्रिप्स के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. इस समय कांग्रेस एवं अन्य संगठनों में दो विचार धाराएं चल रही थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, युद्ध के आरंभ से ही 'दुश्मन का दुश्मन दोस्त' के सिद्धांत पर विश्व युद्ध में ''एक्सिस शक्तियों'' यानी जर्मनी और जापान के हुकूमत से संपर्क कर अंग्रेजों के खिलाफ भूमिगत अभियान में लग गये थे।

जुलाई, 1942 आते–आते ऐसा लगने लगा कि नेताजी की मदद से जापानी सेना बर्मा की तरफ से भारत की अंग्रेजी हुकूमत पर भी हमला करने की तैयारी में थी। इस ऊहापोह की स्थिति में गांधी जी का निर्णायक व्यक्तित्व एक बार फिर उभर कर सामने आया, जब वर्धा की कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गयी. इसी परिप्रेक्ष्य में आठ अगस्त, 1942 को ग्वालिया टैंक मैदान, मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में अंग्रेजी हुकूमत समाप्त करने के लिए भारत से अंग्रेजों के वापसी की मांग का एलान किया गया।

युसूफ मेहर अली द्वारा सुझाया गया नाम था ''भारत छोड़ो आंदोलन'' : युसूफ मेहर अली के द्वारा सुझाये इस नाम ''भारत छोड़ो आंदोलन'' को कई अन्य वैकल्पिक नामों– जैसे 'बाहर जाओ' या 'वापस जाओ'–की तुलना में चुना गया। उधर, अंग्रेजी हुकूमत ऐसी स्थिति से निबटने की तैयारी पहले ही कर चुकी थी और रातों–रात कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार कर लिये गये।

परंतु नौ अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गयी। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सभी जगह हड़ताल एवं उपद्रव से जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया। पूरे देश में हिंसा के वारदात हुए एवं कई स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा समानांतर सरकारों का गठन कर लिया गया. इस आंदोलन में लगभग एक लाख लोग गिरफ्तार किये गये। सैकड़ों लोग मारे गये. फिर भी आंदोलन को अभी निर्णायक मुकाम पर पहुँचना बाकी था। इस बीच 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा जिसमें हजारों लोग भुखमरी एवं महामारी के शिकार हुए. इस कारण आंदोलन धीमा पड़ा। वैसे भी सारे नेताओं के जेल चले जाने या भूमिगत हो जाने के कारण आंदोलनकारियों का नेताओं से संपर्क टूट गया एवं आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया।

इससे आंदोलन संगठित एवं प्रभावी नहीं रह पाया। गांधी जी के आगा खां पैलेस पूना में नजरबंद रहने के काल में ही पत्नी कस्तूरबा एवं उनके निजी सचिव महादेव देसाई का निधन हो गया। इन सब के बावजूद गांधी जी ने जेल में ही अपना प्रसिद्ध 'इक्कीस दिनों का उपवास' रखा जिसकी नैतिक ताकत के समक्ष अंग्रेजी शासन को झुकना पड़ा एवं उपवास तुड़वाया गया। अंत में उनकी शरीरिक दुर्बलता एवं अनिष्ट की आशंका को देखते हुए उन्हें जेल से रिहा किया गया।

यह आंदोलन ऐतिहासिक रूप से मील का पत्थर साबित : बहरहाल, हम भारत छोड़ो आंदोलन का आकलन करें तो तकनीकी रूप से भले यह सफल नहीं दिखता हो परन्तु इसकी विफलता में ही पूर्ण सफलता के सभी तत्व मौजूद थे। कई कारणों से यह आंदोलन ऐतिहासिक रूप से मील का पत्थर साबित हुआ. यह इस आंदोलन का प्रभाव ही था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को अंतिम रूप से एहसास करा दिया कि वे भारत पर अपनी ताकत के बल पर और अधिक दिनों तक हुकूमत नहीं कर सकते हैं।

जनक्रांति कि शुरुआत : पहली बात तो यह है कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन कि विफलता से स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत कि भागीदारी को तो बरकरार रखना चाहती है लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं है। नेहरू, गांधी जैसे लोग भी थे, जो इस फासिस्ट विरोधी युद्ध को किसी भी तरह कमजोर करना नहीं चाहते थे। इस निष्कर्ष पर पंहुच गए थे कि और अधिक चुप रहना यह स्वीकार का लेना है कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता कि इच्छा जाने बिना भारत का भाग्य तय करने का अधिकार है। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ–साफ कहा था कि "मैं रूस या चीन कि हार का औजार बनना नहीं चाहता।" लेकिन 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। क्रिप्स कि वापसी के एक पखवाड़े बाद ही उन्होंनें कांग्रेस सिमिति के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था तथा भारतीय जनता का आह्ववान किया गया था कि जापान का हमला हो,तो वह अहिंसक असहयोग करे। नेहरू अगस्त तक संघर्ष के खिलाफ रहें, पर बाद में वे भी सहमत हो गए।

वर्धा प्रस्ताव : जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई, 1942 ई. को गांधीजी ने 'हरिजन' में लिखा "अंग्रेजो भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ।'' गांधीजी ने अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने कि स्थिति में चुनौती देते हुए कहा " मैं देश को बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन कर दूँगा।।'' 14 जुलाई 1942 ई. में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में गाँधी जी के इस विचार को पूर्ण सर्मथन मिला कि भारत में सांविधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएँ। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने "अंग्रेजो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन कि सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त,1942 को इलहाबाद में 'तिलक दिवस' मनाया गया। इस समय नेहरू जी ने कहा "हम लोग आग से खेलने जा रहे हैं। तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे है। जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है।''

7 अगस्त, 1942 ई. को बंबई के ग्वालियाटैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने की। नेहरू ने "भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव" पेश किया जिसको थोड़े संशोधनो के बाद 8 अगस्त, 1942 ई. को स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के इस एतिहासिक सम्मेलन में गाँधी जी ने 70 मिनट तक भाषण दिए। उन्होंनें कहा कि मैं आप को एक मंत्र देता हूँ "करो या मारो" जिसका अर्थ भारत कि जनता देश कि आजादी के लिए हर ढंग से प्रयन्त करे। बस इस बात का ध्यान रखे कि आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक न हो। उन्होंने कहा "आप लोगों में से प्रत्येक

व्यक्ति को आब से स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि मानो आप स्वतंत्र हो। मैं स्वतन्त्रता से कम किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होऊगा।" गाँधी जी इस अवतार के बारे में पट्टाभि सीतारमैंया ने लिखा है कि " वास्तव में गांधीजी उस दिन अवतार एवं पैगंबर कि प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे।" इस भाषण के दौरान गांधीजी ने कहा था कि "हम अपनी गुलामी स्थाई बनाया जाना नहीं देख सकते।"

गिरफ्तारिया : 8 अगस्त कि मध्य रात्री के बाद ही सरकारने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं गिरफ्तार करने की योजना बनायी। 9 अगस्त की सुबह "आपरेशन जीरों आवर" के तहत कंगेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए।
गांधीजी को पूना के आगा खाँ पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गाँधी को आगा खाँ पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल,डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को बांकीपर जेल (पटना) तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। कांग्रेस को असैधानिक संस्था घोषित कर दिया। जुलसों, धरना, प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया।

समानान्तर सरकारे : विद्रोही 'राष्ट्रीय सरकार' का सर्वोत्तम विवरण मिदनापुर के तमलुक उपसभांग में मिलता है। इसके इतिहासकार सतीश सामंत जैसे स्थानीय कांग्रेसी नेता है। जो तमलुक जातीय के पहले 'सर्वाधिनायक' थे। तमलुक उपसभांग में पहली झड़प 8 सितंबर को हुई जब गाँव वालों ने पहल करके दानीपुर के एक मिल मालिक द्वारा चावल भेजें जाने के प्रयत्न को विफल किया और फिर राष्ट्रवादी सेवकों से मदद माँगी। 29 सितंबर को बड़े सुयोनिजीत ढंग से संचार दृसाधनों पर और पुलिस थानों पर एक साथ हमलें हुए। हमलें के स्थल तमलुक, महिषादल, सुताहाट और नंदीग्राम थे। किन्तु अन्य स्थानों पर भारी रक्त पात हुआ एक ही दिन में 44 लोग मारे गए। 17 सितंबर 1942 को स्थापित भूमिगत ताम्रलिप्त जातीय सरकार का प्रमुख कार्य हो गया। बाद में इस इस सरकार कि शाखाएँ, सुताहट, नंदीग्राम, महिषादल में भी स्थापित कि गई।

सतारा (महाराष्ट्र) : समानांतर सरकारे सबसे ज्यादा दीर्घजीवी साबित हुई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से ही यह क्षेत्र काफी सक्रिय रहा था। आंदोलन की पहले चरण में सरकार के स्थानीय मुख्ययालयों में हजारो लोगों का जुलूस निकाला गया। इसके बाद डाकघरों पर हमला, बैंको को लूट, टेलीग्राफ के तारों को काट देना आदि सिलसिला शुरू हुआ। वाई. बी. चव्हाण यहाँ के प्रमुख नेता थे। लेकिन 1942 के अंत 2,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिए जाने से जनांदोलन की गति रुक गई। 1943 की शुरुआत से भूमिगत कार्यकर्ताओ ने अपने को पुसंगठित करना प्रारम्भ किया और लगभग छरू महीने में उनका संगठन तैयार हों गया। समानांतर सरकार की स्थापना की गई। नाना पाटिल इसके महत्वपूर्ण नेता थे। शराब बंदी लागू कर दी गई। गांधी विवाहों का आयोजन हुआ। गावों में पुस्तकालय खोले गए। सतारा की प्रतिसरकार 1945 तक कायम रहीं।

बलिया : प्रथम समानांतर राष्ट्रीय सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया और गाजीपुर दोनों ही स्थानों पर थोड़े समय के लिए स्थापित की गई। बलिया में दस पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया गया।

आंदोलन में बलिदान : वैसे तो क्रांति के समय की गयी अलग–अलग कार्यवाहियों का लेखा–जोखा देना कठिन है। फिर बी दिसंबरतक सरकारी आंकड़ों से अनुमान हो जाता है। इस दौरान पुलिस ने अलग–अलग स्थानों पर कुछ 600 बार गोली चलायी। इससे 763 व्यक्तियों के मारे जाने और 1941 लोगों के आहत होने को स्वीकार किया। 63 पुलिसकर्मी मारे गये दो हजार से अधिक घायल हुए। 10 अन्य सरकारी मारे गये और 364 आहत हुए। 208 पुलिस थानों को क्षति पहुचायी गयी, 749 दूसरे सरकारी भवनों को काफी नुकसान हुआ। 545 सार्वजनिक भवन तोड़–फोड़ के शिकार हुए। बम विस्फोट की 664 घटनाओं की सूचना मिली और 1319 विस्फोटक सामग्री नष्ट की गयी।, 447 बार सडकों में तोड़–फोड़ की गयी, 173 बार सामूहिक जुर्माने लगाये गये। सरकार ने 2562 लोगों को कोड़े लगाने की सजा दी। 91836 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 108 स्थानीय संस्थाओं को भंग कर दिया गया।

निष्कर्ष :
भारत छोड़ो आंदोलन एक पूर्ण रूप से जनांदोलन था। इस आंदोलन में भारत के सभी वर्गों ने भाग लिया। यह आंदलन एक छोर से दूसरे छोर तक फैला था। यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था। जिसका नेतृत्व आम जनता ने किया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में साफ–साफ कहा गया था कि "ऐसा समय आ सकता है जब निर्देश जारी करना संभव न हो सके या निर्देश लोगों तक पहुँच ही न सके। अगर ऐसा है तो प्रत्येक स्त्री पुरुष जो इस आंदोलन में भाग ले रहे है, जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अपने काम का खुद फैसला करें। इस ऐतिहासिक आंदोलन कि एक बड़ी बात यह रही कि इसके द्वारा आजादी कि माँग राष्ट्रीय आंदोलन कि पहली माँग बन गई। भारत छोड़ो आंदोलन असफल अवश्य रहा। परंतु जनचेतना जगाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

संदर्भ :

1. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, डॉ. ए.के. मित्तल, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2007
2. आधुनिक भारत, एस. के पांडे, सुमित प्रकाशन, इलहाबाद, 2008
3. मैकमिलन, रमेशचन्द्र मजूमदार, नई दिल्ली, 1954
4. आधुनिक भारत (1885–1947), सुमित सरकार, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993
5. आधुनिक भारत का इतिहास, रामलखन शुक्ल, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 1982
6. भारत का स्वतन्त्रता संग्राम, विपिन चंद्र, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 1990